[श्री मनीराम बागड़ी]

अनुसार इस समय वनस्पति तेलों के दाम गिरने चाहिए, क्योंकि आयातित तेलों को भी बाजार में सप्लाई कर दिया गया है। इसके बावजूद भी दाम बढ़ते जा रहे हैं।

हिसाब लगाया जाए, तो 12.36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 16½ किलो वनस्पति की दर 203 रुपए होनी चाहिए, जबकि सरकार ने इससे कहीं अधिक कीमत प्रति-क्विंटल तय की है। एक किलो का भाव 12.36 रुपए इस तरह निकलता है : 55 प्रतिशत आयातित वनस्पति तेल जोड़ने के बाद एक किलो की कीमत 9.71 रुपए होती है और उत्पादन-कर सहित कुल उत्पादन-व्यय आता है 2.65 रुपए प्रति किलो।

पिछले दिनों त्यौहारों का मौसम लगभग एक मास आगे बढ़ जाने के कारण वनस्पति की मांग में कुछ कमी आई थी। अतः वनस्पति मिल-मालिकों द्वारा इसके उत्पादन में लगभग 4,000 टन प्रति मास की कटौती कर दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि वनस्पति मिलों द्वारा उत्पादन में कटौती न की जाती, तो न केवल यह इस समय लोगों को निर्धारित दर से कम पर उपलब्ध होता, बल्कि आने वाले दिनों में भी इसकी कमी न रहती। कुछ मिलों का बंद हो जाना भी इस अभाव का कारण है।

सरकार को वनस्पति के इस कृत्रिम अभाव की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(iv) Need to declare Pathanamthitta district of Kerala as industrially backward district to enable its rapid industrialisation

PROF. P.J. KURIEN (Mavelikara) : The Pathanamthitta district of Kerala is an industrially backward district. This district has the highest percentage of literacy in Kerala and is one of the districts which produce the maximum quantity of cash crops like rubber, cardamom etc. Thus, this district contributes enormously to the foreign exchange earnings of the Government. Besides, a very large number of people from this district are working in gulf countries whose remittances run into hundreds of crores of rupees.

However, this district has no industry worth the name. The problem of unemployment among the educated people is very acute here. The Government of Kerala is presently formulating some schemes for setting up industries with the help of non-resident Indians working in the gulf countries. But the Centre's aid and assistance is very much required in this respect. If this district is declared an industrially backward district, the pace of industrialisation can be accelerated.

Therefore, I would request the Government to declare Pathanamthitta as an industrially backward district and provide all facilities for the rapid industrialisation of this district.

(v) Harassment to public caused by Scooter and taxi drivers

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिल्ली के टैक्सी चालकों एवं स्कूटर चालकों द्वारा मनमानी के फलस्वरूप यात्रियों की असुविधा की ओर खींचना चाहता हूं।

दिल्ली भारत की राजधानी है लेकिन राजधानी में यात्री जितने परेशान हो रहे हैं उतने शायद ही कहीं दूसरी जगह होते हों। दिल्ली में टैक्सी एवं स्कूटर पर कोई नियन्त्रण नहीं है। यात्री से मनमाना पैसा वसूल किया जाता है। एक तो अधिकांश टैक्सी एवं स्कूटर का मीटर खराब है, दूसरे आधे से अधिक टैक्सियों की स्थिति खराब है।

नयी दिल्ली एवं दिल्ली जंक्शन से उतरने वाले यात्रियों को कितनी परेशानी होती है, उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। सभी टैक्सी एवं स्कूटर सिर्फ होटल जाना चाहते हैं जहां पहले से ही उनकी सांठ-गांठ रहती है। उसके अलावा दूसरी जगह जाते ही नहीं हैं। यदि जाते हैं तो

मनमाना पैसा मांगते हैं। मनमाना पैसा नहीं देने पर यात्रियों से झगड़ा करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के आदमी असहाय होकर देखते रहते हैं। इस तरह की वारदातें संसत्सदस्यों के साथ भी होती रहती हैं। बहुत सारे टैक्सी स्टैंड में गाड़ियां खड़ी रहती हैं लेकिन वे जाने से साफ इन्कार कर देते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार लिखित एवं टेलीफोन द्वारा यातायात एस० पी० तथा अन्य अधिकारियों को शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यात्रियों को दिखाने के लिए भले ही शिकायत-पत्र दे दिया जाता है लेकिन उसपर कार्यवाही नहीं होती है। नजदीक से नजदीक जगह पर भी अनजान यात्रियों को चक्कर लगाकर पहुंचाया जाता है और अधिक पैसे वसूले जाते हैं।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि सरकार सभी टैक्सी एवं स्कूटर के मीटर की जांच कराए। जिन गाड़ियों की कन्डीशन खराब है उनका लाइसेंस खत्म करे। मीटर के पुराने अंकित रेट को संशोधित करे जिससे जितना मीटर उठे उतना ही पैसा लिया जाए। यातायात पुलिस को चुस्त-दुरुस्त किया जाए जिससे यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।

(vi) Irregularities in recruitment in Dena Bank of Calcutta region

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly): The Calcutta region of Dena Bank, a nationalised bank is not following any acknowledged policy of recruitment in respect of subordinate staff. There is no regular system of recruitment of subordinate staff in the above bank. The management began notification of vacancies only after the judgement of the Industrial Tribunal dated 2.4.1976. Subsequently, the management started engaging persons on daily wage basis. The head office of Dena Bank clearly instructed, through its letter dated 18.5.1979, that the entire recruitment of subordinate staff be made only through Employment Exchanges. Even after this clear instruction from head office, the Calcutta region of Dena Bank continued to recruit subordinate staff on daily wage basis only. The head office issued a further circular on 6.1.1982 which contained the directives and instructions of the Central Government in this regard.

But except for recruitment in two branches of Dena Bank at Krishnanagar and Berhampore, West Bengal, the Calcutta region continues to disregard the directives and instructions of Central Government for recruitment of subordinate staff through employment exchanges only.

I urge upon the Central Government to ensure that recruitment of subordinate staff is done according to the set rules.

(vii) Need to exempt small huller rice mills of Kerala from the Central Government's order for modernisation of all rice mills in the country

SHRI V.S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat)* : I want to draw the attention of the Government to a problem being faced by the small huller rice mill owners in Kerala.

There are about 13,500 small huller rice mills in Kerala. These mills hull paddy for a charge, and that is the only source of livelihood of the operators of these mills. The average quantity of paddy hulled in these mills is not more than 250 Kg., and the daily income is not more than Rs. 25/-.

The Central Government's order about modernization of all rice mills in the country has dealt a stunning blow to these small mills. Firstly, modernization requires a large amount of capital, which cannot be mobilized by the small operators. Even the spare parts of the mills are so costly that it is often beyond the capacity of these millers to buy them. Secondly, no special advantage will be obtained by modernizing these small mills. Unlike in other States, the consumers in Kerala use boiled rice. Hulling of boiled rice does not result in any wastage. One important consideration which weighed with the Government while directing modernization, was the tremendous wastage of rice which occurs in the process of hulling. This problem does not exist in Kerala.

*Original speech was delivered in Malayalam.